सर्दियों में 4300 मेगावॉट तक जा सकती है बिजली की मांग
पीक डिमांड को पूरा करने के लिए बीएसईएस ने किए पूरे इंतजाम

नई दिल्लीः 19 दिसंबर, 2017। सर्दियों में दिल्ली में बिजली की मांग 4300 मेगावॉट तक पहुंच सकती है। पिछले साल, ठंड के महीनों में दिल्ली में बिजली की पीक डिमांड 4168 मेगावॉट थी। पिछले साल, सर्दियों में बीआरपीएल क्षेत्र में बिजली की पीक डिमांड ने 1758 मेगावॉट के आंकड़े को छुआ था, और बीवाईपीएल क्षेत्र में पीक डिमांड 982 मेगावॉट पहुंच गई थी। इस साल भी, सर्दियों में बिजली की पीक डिमांड इसी रेंज में रहने की उम्मीद है।

सर्दियों में बिजली की मांग का अनुमान लगाने के लिए बीएसईएस ने आईएमडी– पॉस्को की वेदर फोरकास्टिंग तकनीक के साथ–साथ, इन–हाउस एडवांस्ड फोरकास्टिंग मॉड्यूल्स का उपयोग भी कर रही है। इन तकनीकों के इस्तेमाल से बिजली की मांग का लगभग सटीक अनुमान लगाकर उपभोक्ताओं को बिजली की सुचारू आपूर्ति करने में मदद मिलेगी।

बीएसईएस ने बिजली की पीक डिमांड को पूरा करने के सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ठंड के महीनों में बिजली की सुचारू आपूर्ति के लिए, बिजली के पर्याप्त इंतजाम कर लिए गए हैं। लॉन्ग टर्म आधार पर बिजली खरीद समझौतों के तहत, बीएसईएस को पीक डिमांड को पूरा करने के लिए प्र्याप्त बिजली मिलेगी। बीवाईपीएल को पावर बैंकिंग मॉड्यूल के तहत, दिसंबर से फरवरी माह के दौरान उत्तर प्रदेश से 50–100 मेगावॉट अतिरिक्त बिजली मिलेगी। इसके बावजूद, अगर किसी कारणवश अचानक बिजली की मांग बढ़ती है, तो एक्सचेंज से शॉर्ट–टर्म आधार पर बिजली की खरीद की जाएगी।

बीएसईएस ने सर्दियों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के अलावा, अभी से ही गर्मियों की तैयारियां भी शुरू कर दी है। इसके लिए पावर बैंकिंग मॉड्यूल का उपयोग किया जा रहा है। इसके तहत, सर्दियों के दौरान बीआरपीएल पावर बैंकिंग मॉड्यूल के तहत, हिमाचल प्रदेश को 450 मेगावॉट, तमिलनाडु को 20 मेगावॉट और सिक्किम को 50 मेगावॉट बिजली दे रही है। वहीं, बीवाईपीएल पावर बैंकिंग के तहत जम्मू–कश्मीर, मेघालय और झारखंड को सर्दियों के दौरान 240 मेगावॉट बिजली दे रही है। ये राज्य बीआरपीएल और बीवाईपीएल को गर्मियों के दौरान इतनी ही मात्रा में बिजली वापस करेंगे, जिससे गर्मियों में बीएसईएस उपभोक्ताओं को सुचारू बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल और बीवाईपीएल रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच संयुक्त उद्यम हैं।

———